BSNL
Connecting India Faster

Press Media Communication Report

-From Public Relations Cell BSNL CO New Delhi

Publication:	दैनिक जागरण	Page No:	11
Place:	नई दिल्ली	Date:	12/12

बीएसएनएल शुरू करेगा 'मोदी कैश' सेवा

भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर जनवरी में शुरू होगी यह सेवा

नितिन प्रधान, नई दिल्ली

अब स्मार्टफोन ही नहीं ग्रामीण इलाकों में फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले भी अपने मोबाइल से भुगतान कर सकेंगे। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अगले महीने फीचर फोन रखने वाले अपने ग्राहकों के लिए ऐसी ही एक स्कीम लेकर आ रही है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के साथ शुरू की जा रही इस सेवा का नाम 'मोदी कैश' रखे जाने की संभावना है।

नोटबंदी के बाद सरकार लगातार नकदी के कम इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को लोकप्रिय बनाने में जुटी है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल देश में लेस कैश सोसायटी के निर्माण में मदद मिलेगी बल्कि नकदी के रखरखाव पर आने वाली लागत को भी काफी कम किया जा सकेगा। इसके लिए न केवल मोबाइल कंपनियों को बेहतर सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है बल्कि क्रेडिट/डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर कई रियायतों की घोषणा भी की गई है। लेकिन इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू कराने में सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाली ज्यादातर आबादी अब भी पुराने फीचर फोन का इस्तेमाल करती है। जबकि मोबाइल बैंकिंग से लेकर ई-वालेट जैसी तमाम सुविधाएं केवल स्मार्ट फोन पर ही उपलब्ध हैं। ऐसे में उन लोगों तक इन सेवाओं का लाभ पहुंचाने में दिक्कत महसूस की गई।

- स्मार्ट फोन की जगह फीचर फोन से हो सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन

मोबाइल बैंकिंग की तर्ज पर करेगी काम

सूत्र बताते हैं कि इस समस्या का हल निकालने के लिए ही बीएसएनएल और एसबीआइ की इस योजना का खाका तैयार किया गया है। यह काफी हद तक मोबाइल बैंकिंग की तर्ज पर काम करेगी, लेकिन बताया जाता है कि इसे फीचर फोन से एसएमएस के जरिये संचालित किया जा सकेगा। इसमें नकद राशि प्राप्त करने और भुगतान करने दोनों की सुविधा होगी। इसमें ग्राहक एसबीआइ के अपने खाते से किसी को भी केवल एक एसएमएस के जरिये भुगतान कर सकेगा और खाते में राशि भी प्राप्त कर सकेगा। बीएसएनएल अगले महीने इस योजना को लांच करेगा। शुरुआत में यह योजना चार राज्यों में शुरू की जा रही है। अगले तीन-चार महीने में इसे पूरे भारत में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

रविशंकर की अहम भूमिका

सूत्र बताते हैं कि रविशंकर प्रसाद का इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इस सेवा के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने में अहम भूमिका रही है। वैसे भी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश में लेस कैश सौदों की संख्या बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद खुद सब गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। गौरतलब है कि शनिवार को ही मोबाइल कंपनियों के साथ हुई एक बैठक में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किए गए इस अभियान का हिस्सा बनने को कहा गया था।

प्लास्टिक के बड़े नोट भी जारी होंगे

जागरण संवाददाता, जयपुर : केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार प्रायोगिक तौर पर 10 और 20 रुपये के प्लास्टिक नोट जारी करेगी। यह प्रयोग सफल रहा तो बड़े नोट भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग प्रणाली नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार इस दिशा में काम कर रही है। साथ ही भरोसा दिलाया कि अगले सप्ताह स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने जनता से अपील की कि उनके पास छोटी करेंसी है तो उसे ज्यादा से ज्यादा काम में लें।

जयपुर में मेघवाल ने कहा कि विश्व में प्लास्टिक करेंसी की शुरुआत आस्ट्रेलिया ने की थी। उसके बाद लगभग आधा दर्जन से अधिक देशों ने इसे लागू किया है। प्लास्टिक करेंसी से जाली नोटों पर भी अंकुश लग सकेगा। मेघवाल ने कहा कि नोटबंदी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को राहत देने के लिए सरकार ने योजना तैयार की है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए ढांचागत सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बढ़ाने, डाकघरों और जिला सहकारी बैंकों के साथ ही ग्रामीण बिजनेस प्रतिनिधि व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा रहा है।

- केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल का एक सप्ताह में स्थिति सुधरने का दावा

मेघवाल ने दावा किया कि देश में कैशलेस प्रणाली को लागू करने से देश की अर्थव्यवस्था तो सुधरेगी, साथ ही ब्याज दरों और करों में कमी आएगी। इसका सर्वाधिक लाभ देश के आम लोगों को मिलेगा। कैशलेस प्रणाली के कारण देश के सकल घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि होगी। उद्योग जगत द्वारा वर्षों से करों को कम करने की मांग की जा रही थी जो कैशलेस प्रणाली के मजबूत होने से स्वतः ही लागू हो सकेगी।